

11

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर, म०प्र०

प्रकरण क्रमांक 1/नगरानी/छतरपुर/श्रु.रु/2017/3544 सन् 2016-17

श्री दिवाकर श्री प्रो. (श्रु.)
द्वारा आज दि 25/9/17
प्रस्तुत
चक्र
बलक ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर
C23.10.17

दिलीप सिंह तनय वीरमणी सिंह यादव

निवासी राजनगर, तहसील राजनगर,

जिला छतरपुर म०प्र०

NO. NO. 9425/44980
बनाम

--- आवेदक

1. उषा पुत्री छन्नूलाल सोनी

निवासी राजनगर तहसील राजनगर

जिला छतरपुर म०प्र०

2. म०प्र० शासन

--- अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता
1959 विरुद्ध तहसीलदार राजनगर के प्रकरण क्रमांक
24/अ-6-अ/2016-17 में संलग्न अनुविभागीय
अधिकारी (रे०) राजनगर का आदेश दिनांक 26.08.
2017 से दुखित होकर।

25/9/17
दिवाकर श्री प्रो. श्रु.
श्रीमान्

महोदय,

:- प्रकरण का सारांश :-

इस प्रकार है कि ग्राम राजनगर, तहसील राजनगर, जिला छतरपुर म०प्र० की भूमि खसरा नं० 2337/2/1, रकवा 0.035 हे० भूमि चार लोगो मोहनलाल, कल्ला, पिरवा, एवं कट्टा दिमर निवासी राजनगर की थी जिसमें सभी का बराबर क हक था उक्त भूमि मेसे 1 सहखातेदार पिरवा दिमर द्वारा अपने हिस्से की भूमि को अनावेदक क्रमांक 1 को विक्रय की गई जिसमें विक्रय पत्र के दोरान यह गलती हुई की उक्त भूमि में उसका हिस्सा 1/4 यानि की लगभग 9 आ भूमि उसके हिस्से मे थी जबकि उसके द्वारा 11 आरे भूमि का विक्रय कर दिया गया जो कि उसके हिस्से से अधिक थी उक्त विक्रय पत्र के उपरांत तहसीलदार राजनगर द्वारा नामांतरण करते बक्त बगैर खसरा रिकार्ड का अवलोकन किये, किसी भी सहखातेदार को सूचना दि नामांतरण कर

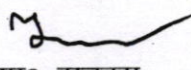
क्रमश // 2 //

XXXIV(4.)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2017/3544

जिला - छतरपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5-12-17	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री दिवाकर दीक्षित उपस्थित । उन्हें ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया । 2/ आवेदक अधिवक्ता के तर्कों पर विचार किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 26-8-17 के विरुद्ध पेश की है जिसके द्वारा उन्होंने तहसीलदार, राजनगर द्वारा नामांतरण पंजी क्रमांक 74/2010 में पारित आदेश दिनांक 28-7-10 के पुनरावलोकन की अनुमति दिया जाना न्यायोचित नहीं माना है तथा यह स्पष्ट किया है कि नामांतरण के विरुद्ध संहिता में अपील/निगरानी के प्रावधान मौजूद हैं व्यथित पक्षकार वरिष्ठ न्यायालय में अपील प्रस्तुत कर सकते हैं । उनका उक्त निष्कर्ष अपने स्थान पर उचित है क्योंकि इस प्रकरण में तहसीलदार के समक्ष पुनरावलोकन का आवेदन उनके पूर्व के आदेश दिनांक 28-7-10 के विरुद्ध वर्ष 12-6-17 को प्रस्तुत किया गया है । इतने लंबे समय उपरांत अपीलीय आदेश के पुनरावलोकन की अनुमति दिया जाना ना तो औचित्यपूर्ण है और ना ही न्यायिक । दर्शित परिस्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के आलोच्य आदेश की पुष्टि करते हुए यह निगरानी अग्राह्य की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो ।</p>	<p> प्रशा0 सदस्य</p>